



# Haryana Government Gazette

## EXTRAORDINARY

Published by Authority

© Govt. of Haryana

No. 18-2015/Ext] CHANDIGARH, MONDAY, FEBRUARY 2, 2015 (MAGHA 13, 1936 SAKA)

हरियाणा सरकार

नगर तथा ग्राम आयोजना विभाग

अधिसूचना

दिनांक 2 फरवरी, 2015

**संख्या पी.एफ-46/1961.**— हरियाणा नगरीय क्षेत्र विकास तथा विनियमन अधिनियम, 1975 (1975 का 8), की धारा 24 की उपधारा (2) के साथ पठित उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा हरियाणा सरकार, नगर तथा ग्राम आयोजना विभाग, अधिसूचना संख्या पी0एफ0-46/14500, दिनांक 3 जुलाई, 2014 के प्रतिनिर्देश से, हरियाणा के राज्यपाल, इसके द्वारा, हरियाणा नगरीय क्षेत्र विकास तथा विनियमन नियम, 1976 को आगे संशोधित करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:—

1. ये नियम हरियाणा नगरीय क्षेत्र विकास तथा विनियमन (संशोधन) नियम, 2014 कहे जा सकते हैं ये 3 जुलाई, 2014 से लागू होंगे तथापि, अनुज्ञप्ति नवीकरण फीस के उदग्रहण के प्रयोजन लिए हरियाणा नगरीय क्षेत्र विकास तथा विनियमन नियम, 1976 के नियम 13 के उपनियम(1) के, अधीन उसी के बाद 4 अप्रैल 2014 से प्रभावी होंगे
2. हरियाणा नगरीय क्षेत्र विकास तथा विनियमन नियम, 1976 में, अंत में, विद्यमान अनुसूची के स्थान पर, निम्नलिखित अनुसूची प्रतिस्थापित की जाएगी, अर्थात्:—

## “अनुसूची

[देखिए नियम 3]

## प्रति सकल एकड़ अनुज्ञप्ति फीस की दरें

(लाख रुपये प्रति सकल एकड़ में)

उपयोग का प्रवर्ग	अति उच्च क्षमता जोन	उच्च-I क्षमता जोन	उच्च-II क्षमता जोन	मध्यम क्षमता जोन	निम्न क्षमता जोन
1	2	3	4	5	6
	गुडगांव- मानेसर अर्बन कम्पलैक्स की विकास योजना के भाग बनने वाले क्षेत्र	फरीदाबाद- बल्लभगढ़ कम्पलैक्स, पिन्जौर- कालका कम्पलैक्स, ग्वाल पहाड़ी तथा पंचकूला को परिधि नियंत्रित क्षेत्र की विकास योजना के भाग बनने वाले क्षेत्र (केवल सभी वाणिज्यिक उपयोग हेतु)	(i) फरीदाबाद- बल्लभगढ़ कम्पलैक्स, पिन्जौर- कालका कम्पलैक्स, ग्वाल पहाड़ी तथा पंचकूला को परिधि नियंत्रित क्षेत्र की विकास योजना के भाग बनने वाले क्षेत्र (सभी वाणिज्यिक उपयोग को छोड़कर);  (ii) सोनीपत-कुण्डली अर्बन एरिया कम्पलैक्स और पानीपत की विकास योजना के भाग बनने वाले क्षेत्र;  (iii) गुडगांव जिले में पड़ने वाली सोहना विकास योजना का भाग; तथा,  (iv) गुडगांव-मानेसर अर्बन कम्पलैक्स की विकास योजना, पटौदी तथा फरुखनगर को विकास योजना के भाग बनने वाले क्षेत्रों को छोड़कर जिला गुडगांव में घोषित नियन्त्रित क्षेत्रों को शामिल करने के लिए, हरियाणा नगरीय क्षेत्र विकास तथा विनियमन अधिनियम, 1975 (1975 का 8) की धारा-2 के खण्ड (ण) के अधीन घोषित कोई अन्य अर्बन क्षेत्र	(i) करनाल, कुरुक्षेत्र, अम्बाला, यमुनानगर- जगाधरी, बहादुरगढ़, हिसार, रोहतक, रेवाड़ी, गन्नौर, पलवल, होडल, बावल धारुहेड़ा तथा पृथला की विकास योजना के भाग बनने वाले क्षेत्र;  (ii) फरीदाबाद जिले में (फरीदाबाद- बल्लभगढ़ कम्पलैक्स के नियन्त्रित क्षेत्र को छोड़कर) तथा पानीपत जिले में तेल रिफाइनरी, पानीपत (बहोली) को छोड़कर पंजाब अनुसूचित सड़क तथा नियन्त्रित क्षेत्र अनियमित विकास निर्बन्धन अधिनियम, 1963 (1963 का पंजाब अधिनियम 41) के अधीन घोषित नियन्त्रित क्षेत्र को शामिल करने के लिए हरियाणा नगरीय क्षेत्र विकास तथा विनियमन अधिनियम, 1975 (1975 का 8) की धारा 2 के खण्ड (ण) के अधीन घोषित अर्बन क्षेत्र	राज्य में सभी अन्य नियन्त्रित क्षेत्र

1	2	3	4	5	6
रिहायशी (प्लाटिड)	12.50	—	9.50	6.25	1.25
रिहायशी (ग्रुप हाउसिंग)	40.00	—	19.00	9.50	2.50
वाणिज्यिक	<p>गुड़गांव —महरौली सड़क पर</p> <p>(i) 150 से उपर फर्श क्षेत्रफल अनुपात के लिए 540</p> <p>(ii) 150 तक फर्श क्षेत्रफल अनुपात के लिए 400.00</p> <p>अन्य सड़कों पर</p> <p>(i) 150 से उपर फर्श क्षेत्रफल अनुपात के लिए 340.00</p> <p>(ii) 150 तक फर्श क्षेत्रफल अनुपात के लिए 270.00</p>	<p>(i) 150 से उपर फर्श क्षेत्रफल अनुपात के लिए 270.00</p> <p>(ii) 150 तक फर्श क्षेत्रफल अनुपात के लिए 235.00</p>	<p>(i) 150 से उपर फर्श क्षेत्रफल अनुपात के लिए 210.00</p> <p>(ii) 150 तक फर्श क्षेत्रफल अनुपात के लिए 140.00</p>	<p>(i) 150 से उपर फर्श क्षेत्रफल अनुपात के लिए 95.00</p> <p>(ii) 150 तक फर्श क्षेत्रफल अनुपात के लिए 62.50</p>	<p>(i) 150 से उपर फर्श क्षेत्रफल अनुपात के लिए 19.00</p> <p>(ii) 150 तक फर्श क्षेत्रफल अनुपात के लिए 12.50</p>
औद्योगिक	2.50	—	1.25	0.625	0.125
निम्न घनत्व पर्यावरण अनुकूल उपनिवेश	25	-----	19	12.50	2.5 , ”,

पी. राघवेन्द्रा राव,  
अतिरिक्त मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार,  
नगर तथा ग्राम आयोजना विभाग

**HARYANA GOVERNMENT**  
**TOWN AND COUNTRY PLANNING DEPARTMENT**

**Notification**

The 2nd February, 2015

**No. PF-46/ 1961.**— In exercise of the powers conferred by Sub-section (1) read with Sub-section (2) of Section 24 of the Haryana Development and Regulation of Urban Areas Act, 1975 (8 of 1975) and with reference to Haryana Government, Town and Country Planning Department, Notification No. PF-46/14500, dated the 3rd July, 2014, the Governor of Haryana hereby makes the following rules further to amend the Haryana Development and Regulation of Urban Areas Rules, 1976, namely:—

1. These rules may be called the Haryana Development and Regulation of Urban Areas (Amendment) Rules, 2014.

They shall come into force with effect from the 4th April 2014. However, for the purpose of levy of licence renewal fees under sub-rule (1) of rule 13 of the Haryana Development and Regulation of Urban Areas Rules, 1976, the same shall come into effect from the 3rd July, 2014.

2. In the Haryana Development and Regulation of Urban Areas Rules, 1976, in the end, for the existing Schedule, the following Schedule shall be substituted, namely:—

**“Schedule**

[See rule 3]

**RATES OF LICENCE FEE PER GROSS ACRE**

(In lacs per gross acre)

Category of Uses	Hyper Potential Zone	High-I Potential Zone	High-II Potential Zone	Medium Potential Zone	Low Potential Zone
1	2	3	4	5	6
	Areas forming part of the development plan of Gurgaon-Manesar Urban Complex.	Areas forming part of Development Plan of Faridabad-Ballabgarh Complex, Pinjore-Kalka Complex, Gwal Pahari & Periphery Controlled area of Panchkula (All for commercial use only)	(i) Areas forming part of Development Plan of Faridabad-Ballabgarh Complex, Pinjore-Kalka Complex, Gwal Pahari and Periphery Controlled area of Panchkula (All for other than commercial use); (ii) Area forming part of Development Plan of Sonapat-Kundli Urban Area Complex and Panipat; (iii) Part of Sohna Development Plan falling in Gurgaon District; and	(i) Areas forming part of Development Plans of Karnal, Kurukshetra, Ambala, Yamuna Nagar-Jagadhari, Bahadurgarh, Hisar, Rohtak, Rewari, Gannaur, Palwal, Hodel, Bawal Dharuhera and Prithla; (ii) The urban areas declared under clause (o) of Section 2 of the Haryana Development and Regulation of Urban Areas Act,	All other urban areas in the State.

1	2	3	4	5	6
			(iv) Any other Urban Area declared under clause (o) of Section 2 of the Haryana Development and Regulation of Urban Areas Act, 1975 (8 of 1975), to cover the Controlled Area declared in Gurgaon District excluding the areas forming part of Development Plan of the Gurgaon-Manesar Urban Complex, Development Plan Pataudi and Farukhnagar.	1975 (8 of 1975) to cover the controlled areas declared under the Punjab Scheduled Roads and Controlled Areas Restriction of Unregulated Development Act, 1963 (Punjab Act 41 of 1963) in Faridabad District (excluding the Controlled Areas of Faridabad-Ballabgarh Complex) and Oil Refinery, Panipat (Baholi) in Panipat District.	
Residential (Plotted)	12.50	—	9.50	6.25	1.25
Residential (Group Housing)	40.00	—	19.00	9.50	2.50
Commercial	<b>On Gurgaon-Mehrauli Road</b> (i) 540.00 for FAR above 150. (ii) 400.00 for FAR upto 150. <b>On other Roads</b> (i) 340.00 for FAR above 150. (ii) 270.00 for FAR upto 150.	(i) 270.00 for FAR above 150. (ii) 235.00 for FAR upto 150.	(i) 210.00 for FAR above 150. (ii) 140.00 for FAR upto 150.	(i) 95.00 for FAR above 150. (ii) 62.50 for FAR upto 150.	(i) 19.00 for FAR above 150. (ii) 12.50 for FAR upto 150.
Industrial	2.50	—	1.25	0.625	0.125
Low-density Eco-friendly colony	25	—	19	12.50	2.5.”.

P. RAGHAVENDRA RAO,  
 Additional Chief Secretary to Government Haryana,  
 Town and Country Planning Department.

**हरियाणा सरकार**

स्कूल शिक्षा विभाग

**अधिसूचना**

दिनांक 2 फरवरी, 2015

**क्रमांक 8/27-2013पी0एस0(2).**—माननीय उच्च न्यायालय द्वारा सिविल याचिका नं० 20545/2009 में पारित आदेश दिनांक 9-4-2013 की अनुपालना में हरियाणा राज्य द्वारा अधिसूचना नं० 8/27-2013 पी0एस0(2) दिनांक 28-01-2014 द्वारा हरियाणा विद्यालय शिक्षा नियम 2003 में नियम 158 क व 158 ख जोड़कर मण्डल स्तर पर मण्डल आयुक्तों की अध्यक्षता में फीस तथा निधि नियामक समिति का गठन किया जा चुका है। इसलिए माननीय उच्च न्यायालय द्वारा माननीय न्यायाधीश श्रीमती किरण आनन्द लाल (सेवानिवृत्त) की अध्यक्षता में गठित अन्तरिम कमेटी की अब आवश्यकता नहीं है। अतः इसे तुरन्त प्रभाव से समाप्त किया जाता है। अब निजी असहायताप्राप्त मान्यताप्राप्त विद्यालयों की फीस एवं निधियों का नियामन उपरोक्त प्रावधान के अनुसार गठित मण्डल स्तरीय कमेटियों द्वारा किया जाएगा।

टी0सी0 गुप्ता,  
प्रधान सचिव,  
हरियाणा सरकार, विद्यालय शिक्षा विभाग।

**HARYANA GOVERNMENT****SCHOOL EDUCATION DEPARTMENT****Notification**

The 2nd February, 2015

**No. 8/27-2013 PS (2).**—In compliance with the order dated 09-04-2013 passed by the Hon'ble High Court in C.W.P. No. 20545 of 2009, the State of Haryana has constituted Fee and Funds Regulatory Committees for Private Un-Aided Recognized Schools under the Chairmanship of Divisional Commissioners at Division Level by inserting Rule 158-A and 158-B in the Haryana School Education Rules, 2003 vide Notification No. 8/27-2013 PS (2) dated 28.01.2014. Therefore, the Committee constituted by the Hon'ble High Court as interim arrangement under the Chairmanship of Hon'ble Mrs. Justice Kiran Anand Lall (Retd.) is no more required. Hence, the same is hereby abolished with immediate effect. Now, the Fee and Funds of the Private Un-Aided Recognized Schools shall be regulated by the Divisional Level Committees in accordance with above provisions.

T.C. GUPTA,  
Principal Secretary to Government Haryana,  
School Education Department.